the case of Shri Vinodanand Jha Vs. State has inter-alia given directions to Doordarshan and Indian based TV channels to discontinue telecast of adult movies and not to telecast any new or fresh commercially sponsored serial or programme w.e.f. 01.08.1996 unless these are certified by the Censor Board for universal screening.

(c) to (e) To counter the impact of foreign satellite channels Doordarshan is endeavouring on a continuing basis to bring about a qualitative improvement in its channels through a phased expansion of its terrestrial network, introduction of the latest state of art equipments and by providing a wholesome fare of predominatly Indian programming at the national and regional levels so as to sustain and increase the interest of the viewers in their programmes.

Financial Assistance to Sick Companies by Public Sector Banks

1593. SHRI SATISH AGARWAL:
SHRI BANGARU LAXMAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have taken a policy decision to mandate the Public Sector Banks to provide financial assistance to sick companies pending with the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR); and

(b) whether Government will reverse this policy in view of the fact that nearly Rs. 12,000 crores have already caused the exchequer in the recapitalisation of the Public Sector Banks during the last three years and this new policy decisions runs counter to the commitment of Government to carry out financial sector reforms?

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) and (b) When sick industrial companies are referred to the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR), banks extend need based support and allow 'holding-on' operations on a case to case basis. Commercial banks have been advised by the Reserve Bank of India that they should not abruptly stop the credit ficilities to such units but should exercise their judgement in regard to continuance of the 'holding-on' operations.

निजी विमान कम्पनियों द्वारा कर का भुगतान न किया जाना

1594. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी विमान कम्पनियों के संचालकों द्वारा यात्रियों से वसूल किए गए कर का भुगतान सरकार को नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितने राजस्व की हानि हुई है;

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप हाल ही में इन विमान कम्पनियों की कतिपय उड़ानों पर रोक लगा दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने निजी विमान कम्पनियों के संचालकों द्वारा यात्रियों से लिए गए कर की समय पर वसूली हेतु क्या कदम उठाए है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) जी, हां। कुछेक निजी विमान कंपनियों ने नियत समय के भीतर अंतर्देशीय वायु यात्रा कर जमा नहीं कराया।

(ख) इसके परिणामस्वरूप कोई राजस्व हानि नहीं हुई, तथापि ऐसे निजी विमान संचालकों से वसूली को जाने तक अंतर्देशीय वायु यात्रा कर की बकाया देय राशियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

अन्तरर्देशीय वायु यात्रा कर की देय राशि	778.21 लाख रुपए
	458.47 लाख रुपए
अर्थदण्ड	479.14 लाख रुपए

(ग) और (घ): यदि करों को समय पर जमा नहीं किया जाता है तो भुगतान न करने वाले ऐसे संचालकों के विमानों का असिधन कर दिया जाता है। अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर की देय राशि की वसूली के लिए पीछे भी 6 विमानों का विभिन्न अवधियों के लिए असिधन कर दिया गया था। संचालकों द्वारा बकाया देय राशियों की अदायगी के पश्चात् उनमें से पांच विमानों को छोड़ दिया